GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
DEPARTMENT OF JUSTICE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 110
ANSWERED ON 01.08.2024

VACANCIES OF JUDGES IN COURTS OF KERALA

*110. SHRI SANDOSH KUMAR P:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the number of vacancies of Judges in the High Court of Kerala, District Courts and Sub-ordinate Courts as of 31st March, 2024;

(b) whether Government has taken any steps to fill the vacant posts in the judiciary in Kerala;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *110 FOR ANSWER ON 01.08.2024 REGARDING 'VACANCIES OF JUDGES IN COURTS OF KERALA.

(a): The Status of vacancies of Judges in Kerala is as under:

S. No.	Name of Court	Vacancy as on 31.03.2024
1	High Court	06
2	District and Subordinate Courts	55*

*Excludes 3 non – judicial deputation posts in the cadre of District and Sessions Judge based on the new policy of High Court restricting deputation to such posts.

(b) to (d): The Judges of High Courts are appointed under Article 217 and 224 of the Constitution of India and according to the procedure laid down in the Memorandum of Procedure (MoP) prepared in 1998 pursuant to Supreme Court Judgement of October 6, 1993 (Second Judges case) read with their Advisory Opinion of October 28, 1998 (Third Judges case).

As per the MoP, the responsibility for initiation of proposals for appointment of Judges in the High Court vests with the Chief Justice of the concerned High Court, in consultation with two senior-most puisne Judges of the High Court. For appointments of judge to the High Court, under the MoP, the views of concerned State Government is also obtained. The recommendations also have to be considered in the light of such other reports as may be available to the Government in respect of the names under consideration. The recommendations of the High Court Collegium, the State Government and the Government of India are then forwarded to the Supreme Court Collegium (SCC) for advice. Only those persons are appointed as Judge of High Courts whose names have been recommended by the SCC.

Appointment of Judges in Supreme Court and High Courts is a continuous, integrated and collaborative process between the Executive and the Judiciary. It requires consultation and approval from various constitutional authorities both at State and Central level. While every effort is made to fill up the existing vacancies expeditiously, vacancies of Judges in High Courts do keep on arising on account of retirement, resignation or elevation of Judges and also due to increase in the strength of Judges.

The filling up of vacant positions in the District Courts of the country is the responsibility of the High Courts and State Governments concerned. As per the Constitutional framework, in exercise of powers conferred under proviso to Article 309 read with Articles 233 and 234 of the Constitution, the respective State Government in consultation with the High Court frames the rules and regulations regarding the issues of appointment and recruitment of Judicial Officers in the respective State Judicial Service. In some States, the respective High Court

undertakes the recruitment process, whereas in other States, the High Court does it in consultation with the State Public Service Commission. The Hon'ble Supreme Court vide judicial order passed in January 2007 in the Malik Mazhar Sultan case, has stipulated certain timelines which are to be followed by the States and the respective High Courts for initiating the recruitment process of judges in subordinate courts.

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *110
जिसका उत्तर गुरुवार, 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

केरल के न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

***110 श्री संदोष कुमार पी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2024 की तारीख तक, केरल उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) क्या सरकार ने केरल की न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

"केरल के न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद" से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *110, जिसका उत्तर 01.08.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : केरल में न्यायाधीशों की रिक्तियों की प्रास्थिति निम्नानुसार है :--

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	31.03.2024 को रिक्तियां
1.	उच्च न्यायालय	06
2.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	55*

* ऐसे पदों पर प्रतिनियुक्ति को निर्बंधित करके उच्च न्यायालय की नई नीति पर आधारित जिला और सेशन न्यायाधीश के काडर में 3 गैर-न्यायिक प्रतिनियुक्ति पदों को अपवर्जित किया गया है ।

(ख) से (घ) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय (दूसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसकी 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ किए जाने की जिम्मेदारी, उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठम अवर न्यायाधीशों से परामर्श करके संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होती है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, प्रक्रिया ज्ञापन के अधीन, संबंधित राज्य सरकार के अभिमत भी अभिप्राप्त किए जाते हैं । ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में ऐसी सिफारिशों पर भी विचार करना होता है, जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हो । फिर, उच्च न्यायालय कोलेजियम, राज्य सरकार और भारत सरकार की सिफारिशें, सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कोलेजियम (एससीसी) को अग्रेषित की जाती है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में केवल उन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जिनके नामों की सिफारिश एससीसी द्वारा की गई है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक सतत्, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसमें राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर, दोनों पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । जबकि विद्यमान रिक्तियां शीघ्रता से भरने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या प्रोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रहती है ।

देश के जिला न्यायालयों में रिक्त स्थानों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । सांविधानिक कार्यढ़ांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करके, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मुद्दों के संबंध में नियम और विनियम बनाती है । कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया का जिम्मा लेते हैं, जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय इसे राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से करता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहार सुल्तान मामले में वर्ष 2007 में पारित न्यायिक आदेश द्वारा कुछ समयसीमाएं नियत की हैं, जिनका अधीनस्थ न्यायालयों को, न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना है ।

*****

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.3, Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my supplementary to the Ministry is that Kerala Assembly has passed unanimous resolution twice for a Bench of the High Court in Trivandrum. That is the capital city of Kerala. The neighbouring States like Tamil Nadu and Karnataka...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, focus on the question.

DR. JOHN BRITTAS: So, my question is this. As there are multiple Benches, even in neighbouring States, the capital city is deprived of a High Court Bench.

MR. CHAIRMAN: You have made your point.

DR. JOHN BRITTAS: Will the Government take initiative in ensuring that?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति महोदय, यह जो प्रश्न संख्या 110 है। यह केरल हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसी है और केरल स्टेट में Subordinate Courts में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उससे संबंधित है। फिर भी इन्होंने पूछा कि क्या केरल में प्रिंसिपल बेंच के अलावा कोई और बेंच स्थापित हो सकती है? इस मामले में सर आपको भी पता है कि संबंधित हाई कोर्ट जब इसमें exercise करता है, फिर राज्यपाल की राय, मुख्य मंत्री की राय और सबकी राय आती है, उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट तय करता है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.4; Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, the question is about the appointment of Judges in the High Court and the Subordinate Court. As per the Supreme Court ruling in 1993 in the Second Judge's Case, it is a Collegium System which appoints the Judges. Now, when the recommendation of the High Court comes to the Supreme Court, the Supreme Court Collegium recommends it to the Central Government and the Central Government appoints the judges. Now, the Central Government can send the recommendation back to the Supreme Court collegium. But, the judgment specifically states that once it is sent back and the Supreme Court reiterates it back to the Central Government, then it is mandatory that you have to appoint. Sir, you have been a lawyer, and I am also a lawyer. I have seen you as a senior lawyer in the Supreme Court running from one court to another.

MR. CHAIRMAN: Please ask the supplementary.

SHRI HARIS BEERAN: Yes, Sir. There are six vacancies in the High Court as per the statement of the hon. Minister. There are two cases of recommendations, which were made by the High Court, and the Supreme Court Collegium also had approved those particular recommendations and sent it to the Central Government. *

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

SHRI HARIS BEERAN: These two recommendations have already been made to the Central Government. The Union Government is not appointing those judges. Not only that, those...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief. You have asked your question.

SHRI HARIS BEERAN: Just 30 seconds. * another Judge, another gentleman who has been reiterated, also has not been appointed. My question is: What is the reason for non-appointment of Judges despite the recommendation?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: उपसभापति महोदय, यह केरल हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न था। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की टोटल sanctioned strength है, वह 1,114 है। उसमें से 754 वैकेन्सीज़ भरी हुई हैं। अब जो खाली वैकेन्सीज़ हैं, माननीय सदस्य हाई कोर्ट जजेज़ की बात कर रहे हैं, तो 360 है। 205 नाम अलग-अलग हाई कोर्ट्स collegium से हमारे पास आए हैं और वे विचाराधीन हैं और 155 वैकेन्सीज़ के लिए अभी तक हाई कोर्ट से नाम ही नहीं आए हैं। वैसे ही ये किसी जज का नाम नहीं ले सकते, फिर केरल में इन्होंने जो कहा है, जो वैकेन्सी है, उसके तहत हमारे पास जो प्रपोजल पेंडिंग है, proposal for appointment of four Judicial Officers as Judges of Kerala High Court received in Department of Justice on 4th June, 2024. And, the second proposal has two names, one advocate and one judicial officer, recommended by the Supreme Court Collegium on 10.10.2023 and 16.04.2024

* Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

respectively. वह अंडर कंसीडरेशन है। एक प्रपोजल, जो केरल हाई कोर्ट से संबंधित है, for appointment of Chief Justice of Kerala High Court, recommended by the Supreme Court Collegium of India on 11th July, 2024. ये सब अंडर कंसीडरेशन हैं, जल्दी इसमें निर्णय लिए जाएंगे।

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्य ने जो जज का नाम लिया है, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। Dr. Sasmit Patraji; fifth and last supplementary.

DR. SASMIT PATRA: Sir, my specific question to hon. Minister is that Supreme Court collegium and its workings, which he has referred to in his reply...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Question is on vacancy of Judges in High Courts in Kerala.

DR. SASMIT PATRA: Absolutely, Sir. So, I am referring to primarily appointment of Judges in High Courts specifically. It was felt that the Supreme Court and its appointments at the Supreme Court through the Collegium has been 100 per cent. There are no vacancies. But, when it comes to High Courts, the Collegium, though sits several times, it is seen that regarding appointment of Judges in the High Courts, the disposal rate is not so much as compared to that which is taken up. So, is this matter being taken up with the Collegium, through the hon. Chief Justice, at times, with the Government to see expeditious appointment of High Court Judges, where as compared to the Supreme Court, 100 per cent filling of vacancy has been done?

श्री अर्जुन राम मेघवालः महोदय, यह क्वेश्चन से ज्यादा सुझाव है। जैसा मैंने पहले का कि 1,114 sacntioned strength है, जिसमें 754 वैकेन्सीज हमारी भरी हुई हैं। 360 हाई कोर्ट्स में जो वैकेन्सीज़ हैं, उसमें हमारे पास 205 नाम आए हैं और 155 के नाम नहीं आए हैं। इनका सुझाव यह है कि High Court collegium जब नाम भेजें, तो एक प्रक्रिया है कि वैकेन्सी होने के छह महीने पहले भेजें, तो वह विषय हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कन्सल्टेशन के लिए ले जाएंगे। आपका सुझाव अच्छा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Five supplementaries are over. Now, Q.No.111. Shri C.Ve. Shanmugam - not present. Any supplementaries?